



सां/No.: 5-1(426)/2017-PD

दिनांक/Dated: 07.06.2017

प्रेषक / From:

संयुक्त सचिव (प्रशासन)  
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To :

The Directors / Heads of all  
National Labs./Instts. of CSIR  
Hqrs./Complex/Centres/Units

महोदय/Sir / महोदया/Madam,

मुझे भारत सरकार के निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापन को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

I am directed to forward herewith the following Office Memorandum for information, guidance and compliance.

क्रम सं. S. No	कार्यालय ज्ञापन सं / OM No.	विषय/ Subject
1	Govt. of India, MoPPG&P, DoPT OM No. 11012/4/2016-Estt(A) dated 23.08.2016.	Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 – instructions regarding timely issue of Charge-sheet- reg

भवदीय/Yours faithfully,

- विनोद कुमार  
07/6/17

(विनोद कुमार /Vinod Kumar)  
अवर सचिव (नीति प्रभाग) / US(PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above  
प्रतिलिपि/Copy to:

- 4) Head, IT Division with the request to make this communication available on the website & Policy Repository.
- 2) कार्यालय प्रति/Office copy

F. No. 11012/04/2016-Estt.(A)  
Government of India  
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions  
Department of Personnel & Training  
Establishment A-III Desk  
\*\*\*\*\*

North Block, New Delhi — 110001  
Dated August 23, 2016

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965-instructions regarding timely issue of Charge-sheet - regarding.

The undersigned is directed to refer to DoP&T's O.M. No. 11012/17/2013-Estt.A-III dated 3<sup>rd</sup> July, 2015 on the above mentioned subject and to say that in a recent case, *Ajay Kumar Choudhary vs Union of India Civil Appeal No. 1912 of 2015 dated 16/02/2015*, the Apex Court has directed as follows:

*"14 We, therefore, direct that the currency of a Suspension Order should not extend beyond three months if within this period the Memorandum of Charges/Chargesheet is not served on the delinquent officer/employee; if the Memorandum of Charges/Chargesheet is served a reasoned order must be passed for the extension of the suspension. As in the case in hand, the Government is free to transfer the concerned person to any Department in any of its offices within or outside the State so as to sever any local or personal contact that he may have and which he may misuse for obstructing the investigation against him. The Government may also prohibit him from contacting any person, or handling records and documents till the stage of his having to prepare his defence..... Furthermore, the direction of the Central Vigilance Commission that pending a criminal investigation departmental proceedings are to be held in abeyance stands superseded in view of the stand adopted by us."*

2. In compliance of the above judgement, it has been decided that where a Government servant is placed under suspension, the order of suspension should not extend beyond three months, if within this period the charge-sheet is not served to the charged officer. As such, it should be ensured that the charge sheet is issued before expiry of 90 days from the date of suspension. As the suspension will lapse in case this time line is not adhered to, a close watch needs to be kept at all levels to ensure that charge sheets are issued in time.

3. It should also be ensured that disciplinary proceedings are initiated as far as practicable in cases where an investigating agency is seized of the matter or criminal proceedings have been launched. Clarifications in this regard have already been issued vide O.M. No. 11012/6/2007-Estt.A-III dated 21.07.2016.

Contd...

4. All Ministries/ Departments/Offices are requested to bring the above guidelines to the notice of all Disciplinary Authorities under their control.

5. Hindi version will follow.

  
(Mukesh Chaturvedi)  
Director (E)  
Tel: 23093176

To  
Secretaries of all Ministries/ Departments

Copy to:

1. President's Secretariat, New Delhi.
2. Vice-President's Secretariat, New Delhi.
3. The Prime Minister's Office, New Delhi.
4. Cabinet Secretariat, New Delhi.
5. Rajya Sabha Secretariat/Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
6. The Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
7. The Secretary, Union Public Service Commission, New Delhi.
8. The Secretary, Staff Selection Commission, New Delhi.
9. All attached offices under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
10. Secretary, National Council (JCM), 13, Feroze Shah Road, New Delhi.
11. CVOs of all Ministries/Departments.
12. ADG (M&C), Press Information Bureau, DoP&T
- ✓ 13. NIC, Department of Personnel & Training, North Block, New Delhi (for uploading the same on the website of this Ministry under the Head OMs & Orders → Establishment → CCS(CCA) Rules and "what is new".
14. Hindi Section, DoP&T

  
(Mukesh Chaturvedi)  
Director (E)  
Tele: 2309 3176



फा. सं. 11012/04/2016-स्था.(क)  
भारत सरकार  
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग  
स्थापना क-III डेस्क  
\*\*\*\*

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001  
दिनांक: 23 अगस्त, 2016

कार्यालय जापन

**विषय :** केंद्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 - आरोप पत्र समय पर जारी करने संबंधी अनुदेशों के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 3 जुलाई, 2015 के कार्यालय जापन सं. 11012/17/2013-स्था.क-III का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि हाल ही में अजय कुमार चौधरी बनाम भारत संघ सिविल अपील सं. 2015 की 1912 दिनांक 16/02/2015 मामले में शीर्ष न्यायालय ने निम्नलिखित निदेश दिया है:

*"14 अतः हम निदेश देते हैं कि किसी निलंबन आदेश का प्रवर्तन तीन माह से अधिक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए यदि इस अवधि के भीतर आरोपों का जापन/आरोप पत्र कसूरवार अधिकारी/कर्मचारी को नहीं दिया जाता है; यदि आरोपों का जापन/आरोप पत्र दिया जाता है तो निलंबन में विस्तार करने के लिए एक तर्कसंगत आदेश अवश्य जारी किया जाना चाहिए। जैसे कि इस मामले में, सरकार संबंधित व्यक्ति को राज्य में या राज्य से बाहर इसके किसी भी कार्यालय में किसी भी विभाग में स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र है ताकि उसे उसके किसी भी स्थानीय या व्यक्तिगत संपर्क से अलग किया जा सके जिसका वह उसके विरुद्ध अन्वेषण में बाधा डालने के लिए दुरुपयोग कर सकता है। सरकार उसे उसका बचाव तैयार करने की अवस्था तक किसी भी व्यक्ति से संपर्क करने अथवा रिकॉर्ड और दस्तावेजों का प्रबंधन करने से भी रोक सकती है। ..... इसके आलावा, केंद्रीय सतर्कता आयोग के इस निदेश कि आपराधिक अन्वेषण के लंबित होने से विभागीय कार्यवाही को भी मुलतवी रखा जाए, का हमारे द्वारा अपनाए गए इस दृष्टिकोण के मद्देनजर अधिक्रमण किया जाता है।"*

2. उपर्युक्त निर्णय के अनुपालन में, यह निर्णय लिया गया है कि जहां कहीं किसी सरकारी कर्मचारी को निलंबनाधीन रखा जाता है तो निलंबन के आदेश को तीन माह से अधिक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, यदि इस अवधि के भीतर आरोपित अधिकारी को आरोप-पत्र नहीं दिया जाता है। इस प्रकार, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आरोप-पत्र निलंबन की तारीख से 90 दिनों के मियाद के पूर्व जारी किया जाए। चूंकि यदि इस समय-सीमा का पालन नहीं किए जाने पर निलंबन समाप्त हो जाएगा, अतः आरोप पत्र का समय पर जारी होना सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर कड़ी नजर रखना आवश्यक है।

3. यह भी सुनिश्चित किया जामा चाहिए कि ऐसे मामलें में जहां किसी अन्वेषण एजेंसी ने मामले का अधिग्रहण कर लिया है या आपराधिक कार्यवाही शुरू का दी गई है वहां यथा व्यवहार्य अनुशासनिक कार्यवाही शुरू कर दी जाए। इस संबंध में दिनांक 21.07.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11012/6/2007-स्था.क के तहत स्पष्टीकरण भी जारी किए जा चुके हैं।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों से अनुरोध किया जाता है कि वे उपर्युक्त दिशानिर्देशों को अपने नियंत्रणाधीन सभी अनुशासनिक प्राधिकारियों के संज्ञान में लाएं।



(मुकेश चतुर्वेदी)

निदेशक (ई)

दूरभाष : 23093176

सेवा में,

सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
2. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
6. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली ।
7. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
8. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली ।
9. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय ।
10. सचिव, राष्ट्रीय परिषद् (जेसीएम), 13 फिरोज़ शाह रोड, नई दिल्ली ।
11. सभी मंत्रालयों/विभागों के केंद्रीय सतर्कता अधिकारी ।
12. एडीजी (एमएंडसी), प्रेस सूचना ब्यूरो, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ।
13. एमआईसी, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (इस कार्यालय ज्ञापन को इस मंत्रालय की वेबसाइट पर कार्यालय ज्ञापन और आदेश-स्थापना-सीसीएस (सीसीए) नियमावली और "नया क्या है" के शीर्षक के अधीन अपलोड करने के लिए)



(मुकेश चतुर्वेदी)

निदेशक (ई)

दूरभाष : 23093176